सैर के लिए खुले एनडीआरआई के द्वार, जनता ने जताया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार

- सुबह सैर करने स्वयं पहुंचे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद
- सैर करने पहुंची जनता ने जगमोहन आनंद को किया धन्यवाद

सुरेन्द्र पांचाल भेदी नजर करनाल, 20 दिसंबर- करनाल शहर की जनता के लिए आखिरकार एनडीआरआई के द्वार सैर करने के लिए शुक्रवार को खुल गए। सुबह-सुबह सैर करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके साथ-साथ करनाल के विधायक जगमोहन आनंद भी पहुंचे। आमजन ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण व करनाल के विधायक जगमोहन आनंद का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हीं की बदौलत एनडीआरआई के गेट आमजन के लिए खुले हैं।

करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि हर रोज प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 7.30 बजे तक एनडीआरआई के अंदर सैर कर सकेंगे। अब शहरवासी सुबह व शाम को सैर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि करनाल वासियों से जुड़ी समस्याओं का हल करवाना उनकी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में करनाल शहर में निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की कोई समस्या है तो वह सीधे उनके कैंप कार्यालय में संपर्क कर सकता है।

विधायक जगमोहन आनंद ने की आमजन के साथ सैर, बाद में ली चाय की चुस्की

विधायक जगमोहन आनंद सुबह-सुबह 5 बजे सैर के लिए एनडीआरआई गेट पहुंच गए थे। वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने विधायक का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने सभी से मुलाकात की और उनके साथ एनडीआरआई में सैर की। इसके उपरांत उन्होंने आमजन के बीच बैठकर चाय पी। उन्होंने कहा कि करनाल शहर का विकास उनके लिए सर्वोपरि है। शहर से जुड़े सभी विकास कार्यों की निरंतर समीक्षा हो रही है, इन कार्यों में और तेजी लाई जाएगी।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के वर्करों सहित निजी व्यक्तियों को नगर निगमों/ परिषदों के मतदान के दौरान पोलिंग बूथों के बाहर वीडीयोग्राफी की अनुमति

चंडीगढ़, 20 दिसंबर- राज्य चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और आम लोगों को तारीख 10. 10. 2024 के हुक्मों अनुसार विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के वर्करों समेत निजी व्यक्तियों की तरफ से पोलिंग स्टेशनों के बाहर वीडीयोग्राफी करने की अनुमति होगी।

इस सम्बन्धी यह भी स्पष्ट किया गया है कि पोलिंग स्टेशनों के अंदर किसी भी निजी व्यक्ति को वीडीयोग्राफी करने की इजाज़त नहीं होगी। आयोग द्वारा यह हिदायतें माननीय हाईकोर्ट (डीबी) द्वारा 24. 5. 2012 को 2012 के सीडबल्यूपी 9601 के कृष्ण कुमार और अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब के हुक्मों के अंतर्गत दी गई हैं। उक्त केस का संचालन भाग निम्नलिखित अनुसार है- ''पटीशनर या कोई अन्य व्यक्ति अपने खर्चे पर पोलिंग स्टेशन के बाहर वीडीयोग्राफी का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र है और यदि वह ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं, तो उनको ऐसा करने से रोका नहीं जायेगा। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि पोलिंग बूथों के अंदर पोलिंग की गोपनीयता बनाये रखने के लिए वीडीयोग्राफी की इजाज़त नहीं होगी।'' उक्त हुक्मों अनुसार, राजनैतिक पार्टियों के निजी व्यक्तियों/ वर्करों द्वारा अपने खर्चे पर वीडीयोग्राफी की इजाज़त दी जाती है, परन्तु यह वीडीयोग्राफी पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के घेरे से बाहर की जानी चाहिए।

पंजाब सरकार द्वारा नगर निगम चुनावों के मद्देनजर 21 दिसंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान

चंडीगढ़, 20 दिसंबर, 2024- नगर निगमों के आम/उप चुनाव-2024 के संबंध में पंजाब राज्य चुनाव आयोग की सिफारिशों पर पंजाब सरकार ने 21 दिसंबर (शनिवार) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत नगर निगमों के माल अधिकार क्षेत्र, जहां चुनाव होने जा रहे हैं, में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है।

इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार ने उन मतदाताओं के लिए भी 21 दिसंबर, 2024 को विशेष छुट्टी का ऐलान किया है जो पंजाब सरकार के कार्यालयों/बोर्डों/कॉर्पोरेशनों/शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे हैं। मतदाता, नगर निगम चुनावों के दौरान अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य अधिकारी को अपना वोटर कार्ड दिखाकर इस विशेष छुट्टी का लाभ ले सकते हैं और यह विशेष छुट्टी उनके छुट्टी खाते में से नहीं काटी जाएगी।

पंजाब विधानसभा स्पीकर ने ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख व्यक्त किया

चंडीगढ़, 20 दिसंबर- पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

एक प्रेस बयान में स संधवां ने चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय राजनीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान और हरियाणा के पांच बार मुख्यमंत्री के रूप में किए गए कार्यों को याद किया।

89 वर्षीय श्री चौटाला, भारत के छठे उपप्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के पुत्र और इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो थे। स संधवां ने हरियाणा के लोगों के प्रति चौटाला की समर्पण भावना की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा।

स्पीकर ने चौटाला के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस कठिन समय का सामना करने की शक्ति प्रदान हो।

4,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पटवारी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 20 दिसंबर, 2024 पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान शुक्रवार को गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में तैनात माल पटवारी हरजीत राय को 4,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बटाला तहसील के गांव नसीरपुर के निवासी सुरिंदर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एक ऑनलाइन शिकायत की जांच के बाद उपर्युक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त पटवारी ने जमीनी जमीन का इंतकाल रोकने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जो कि पटवारी ने पहले शिकायतकर्ता के भतीजे के हक में दर्ज की थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो के थाना अमृतसर रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा और इस मामले की और जांच जारी है।

किसान कालाबाजारी में खरीद रहा है डीएपी खाद, एक जनवरी से सरकार बढ़ाने जा रही है दाम

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के सब्र की परीक्षा ले रही है, उनकी मांग मानने के बजाय कभी लाठी बरसवाती है तो कभी पानी की बौछार तो कभी आंसू गैस के गोले दागती है पर देश का अन्नदाता किसान न तो डरेगा और न ही झुकेगा, न हताश है और न ही बेबस है। आज भी किसान डीएपी खाद के संकट से जूझ रहा है, फसलों की बिजाई के लिए उसे यह खाद ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है तो दूसरी ओर सरकार एक जनवरी-2025 से डीएपी खाद के दाम और बढ़ाने जा रही है। एक ओर जहां फसलों का लागत मूल्य बढ़ रहा है तो उस हिसाब से किसानों को उसकी फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा है। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों का आंदोलन आज भी जारी है पर सरकार है कि किसानों की अनदेखी करने में लगी हुई है, वार्ता के नाम पर किसानों के साथ खेल किया जा रहा है। सरकार को किसानों से बातचीत के लिए समय निकालना ही होगा, साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के सब्र की परीक्षा न लें।

उन्होंने कहा कि सरकार डीएपी खाद का संकट आज तक दूर नहीं कर पाई है तो दूसरी ओर इस खाद पर कालाबाजारी जारी है, 1×50 वाला डीएपी खाद का बैग किसानों को 1800 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। डीएपी की कमी से किसान सरकारी आपूर्ति पर निर्भर हैं, लेकिन इसकी सीमित उपलब्धता के कारण कुछ किसान प्राइवेट मार्केट का सहारा ले रहे हैं। यहां पर डीएपी के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां सरकारी दरों पर खाद्य मिलना मुश्किल हो रहा है, वहीं प्राइवेट विक्रेता डीएपी के एक कट्टे के लिए 1800 से 1900 रुपये तक वसूल रहे हैं। इस कालाबाजारी का सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है, क्योंकि ऊंची कीमतों पर खाद खरीदना उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है।

डीएपी की कमी से फसल उत्पादन पर संभावित असर - डीएपी की कमी का सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ सकता है। समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर बुरा असर पड़ता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। डीएपी की अनुपलब्धता के कारण फसलों की बुवाई प्रक्रिया बाधित हो रही है, जो कि उनकी खेती की आय का प्रमुख स्रोत है। बुवाई में देरी से फसल का उत्पादन समय पर नहीं हो पाएगा, जिससे किसानों की आय में गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। डीएपी खाद की किल्लत को देखते हुए, शासन और प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

एक जनवरी 25 से बढ़ाए जा रहे हैं डीएपी खाद के दाम - मौजूदा समय में डीएपी खाद के एक बैग की कीमत 1350 रुपये है पर एक जनवरी -25 से इस बैग का दाम 1590 रुपये किया जा रहा है। टीएसपी-46 प्रतिशत का दाम 1300 से बढाक़र 1350, 10-26-26 का दाम 1470 से 1725 और 12-31-16 का दाम 1470 से बढाक़र 1725 रुपपे किया जा रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि डीएपी खाद के दाम बढाक़र सरकार किसानों के जख्मों पर नमक छिडक़ रही है। खाद के दाम बढऩे से फसलों का लागत मूल्य भी बढ़ेगा पर विड़बना ये है कि फसलों के लागम मूल्य को देखते हुए भी सरकार फसलों का दाम नहीं बढ़ा रही है और न ही एमएसपी पर कानून ला रही है।

बीपीएल परिवारों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय का गोलमोल जवाब - सांसद कुमारी सैलजा ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर पूछा था कि बीपीएल प्रणाली में विसंगतियों को दूर करने की दिशा में सरकार ने कोई कदम उठाया है, सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि बीपीएली योजनाओं का लाभ जरूरतंद तक कैसे पहुंचेगा, और बीपीएल परिवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी कैसे हो रही है। सांसद के इन जवाबों पर परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार की है, पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नहीं बताया कि बीपीएल परिवारों की संख्या कैसे बढ़ रही है जबकि सरकार का दावा है कि देश में गरीबों की संख्या पहले से कम हुई है।

सांघी गांव के लोगों ने जयहिन्द के सामने रखी अपनी समस्याएं

जयहिन्द बोले भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा साहब को गांव की समस्या का समाधान करवाना चाहिए

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। जैसा कि आप सभी जानते है कि जयहिन्द सेना द्वारा योद्धा खानदान जयहिन्द को रोटीड्डदान मुहीम चलाई गई है। इसी कड़ी में वीरवार 19 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी के गांव सांघी से बुजुर्ग विधवा महिला बबली बाल्मीकि ने नवीन जयहिन्द को अपने घर बुलाकर खाना खिलाया और ग्यारह सौ रुपए का दान दिया जिन्हें जयहिंद ने वहां अपनी समस्या लेकर आई महिलाओं को दे दिए। आपको बता दें कि बबली अपनी कटी हुई विधवा पेंशन की समस्या लेकर जयहिन्द के पास आई थी जिसके बाद जयहिन्द बबली के साथ रोहतक डीसी ऑफिस गए थे। और बाद में उनकी कटी हुई पेंशन बनी व साथ ही जो पेंशन रुकी हुई थी वह भी मिली। जब जयहिन्द बबली के घर खाने पर पहुंचे तो आस पास की ओर भी महिलाएं उनको अपनी समस्या बताने उनके पास पहुंची। उन्होंने बताया कि जिनके अच्छे घर बने हुए है उनके तो पैसे पास कर दिए और जिनके घर टूटने की कागार पर है उनके नहीं किए।

हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती।

जयहिन्द ने बबली का घर देखा जो कि बहुत जर्जर हालत में था, कड़ियों की छत जो कि आधी टूटी हुई थी, और बाकी की भी कब गिर जाए कुछ पता नहीं। एक ओर महिला के घर गए जिनके घर के भी ऐसे ही हालत थे। महिलाओं ने बताया कि ऐसे सिर्फ दो घर नहीं है बल्कि 40 से 50 घर ऐसे है जो कभी भी गिर सकते है। इस पर जयहिन्द ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अपील करते हुए कहा कि आप सांसद है और यह तो आपका पैतृक गांव है, आपके ही गांव में लोग इन हालातों में अपना जीवन यापन कर रहे है आपको सोचना चाहिए और यह आकर इनके हालात देखने चाहिए। साथ ही जयहिन्द ने रोहतक के नए डीसी साहब से भी अपील करी कि आपको अलगड्डअलग गांव के दौरे करने चाहिए ताकि यह पता चले कि योजनाएं लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती।

जो भी आज हरिजन, प्रजापत, बाल्मीकि व अलगड्डअलग समाज के नेता बने घूमते है उनसे भी जयहिन्द ने अपील करते हुए कहा कि आपको यहां आकर इन लोगों के हालात देखने चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। लोगो की समस्याएं सुन कर जयहिन्द ने कहा मै एक दिन का समय निकाल कर दोबारा आपके गांव सांघी में आऊंगा और सबकी समस्याएं सुनूंगा। जयहिन्द ने 7027ड्ड822ड्ड822 नंबर जारी करते हुए बताया कि जो भी साथी जयहिन्द सेना से जुड़ना चाहता है वह हमारे इस नंबर पर कॉल करके हमसे सीधा जुड़ सकता है।

मुख्य सचिव ने 'समाधान शिविर' के माध्यम से जवाबदेह शासन पर दिया बल

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज जन शिकायतों को शीघ्र और निर्धारित समय-सीमा के भीतर हल करने के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दृष्टिकोण से प्रेरित प्रमुख पहल 'समाधान शिविर' की प्रगति की समीक्षा की। इस पहल की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उपायुक्तों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डॉ. जोशी ने कहा कि प्रशासन और लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए शिकायतों का समय पर और कुशलतापूर्वक ढंग से समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा, 'इन शिविरों को शिकायतों के समाधान से आगे बढ़कर उत्तरदायी और समावेशी शासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होना चाहिए।

डॉ. जोशी ने कहा कि अधिकारियों और नागरिकों के बीच सीधे संपर्क की आवश्यकता है ताकि नीति-निर्धारण प्रक्रिया में जनता की प्रतिक्रिया को तत्परता से शामिल किया जा सके। उन्होंने समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने और ठोस परिणाम हासिल करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय बढ़ाने का भी आह्वान किया, ताकि जनता की संतुष्टि बढ़े। उपायुक्तों ने इस कार्यक्रम के प्रति अपने पूर्ण एवं प्रतिबद्ध प्रयासों का आश्वासन देते हुए कहा कि इस पहल से समयबद्ध तरीके से जन शिकायतों के समाधान में सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। बैठक में कार्मिक, प्रशिक्षण एवं संसदीय कार्य विभाग के विशेष सचिव श्री आदित्य दहिया समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंजाब सरकार द्वारा 'कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे' पर किसान संघों के साथ महत्वपूर्ण बैठक

- कृषि नीति के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा
- किसानों के हित प्रभावित नहीं होंगे-कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। प्रदेश के किसानों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री मा. पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हुए। गुरमीत सिंह खुडियन ने विभिन्न किसान संघों के नेताओं को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार ÷कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे÷ से किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी। कृषि मंत्री ने आज यहां पंजाब भवन में ÷कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे÷ के मसौदे पर किसान संघों के नेताओं के साथ गंभीर चर्चा की।

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए मसौदे को लेकर चिंतित है क्योंकि इसका राज्य और उसके किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण वे मसौदा नीति के हर पहलू का गंभीरता से विश्लेषण करेंगे और संबंधित पक्षों से परामर्श करेंगे। .चर्चा करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इस मसौदे का गहराई से अध्ययन करने के लिए आने वाले दिनों में कृषि विशेषज्ञों और अन्य साझेदारों से भी सलाह ली जाएगी ताकि कोई भी पहलू छूट न जाए. एस। गुरमीत सिंह खुडियां, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण

श्री अनुराग वर्मा, पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुखपाल सिंह, पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव श्री रामवीर भी उपस्थित थे, उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इस ड्राफ्ट के संबंध में अपने सुझाव और टिप्पणियाँ कृषि विभाग को भेजें।

जोगिंदर सिंह उगराहां, बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ. दर्शन पाल, रुलदू सिंह मानसा। डॉ। सतनाम सिंह अजनाला और अन्य नेताओं ने इस नीति की आड़ में संभावित निजीकरण, एकाधिकार प्रथाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह नीति तीन कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को फिर से लागू करने का एक प्रयास हो सकती है, जिन्हें केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध के बाद रद्द कर दिया था। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र को जवाब भेजने से पहले इस नीति के सभी पहलुओं की गहनता से जांच करने का आग्रह किया ताकि पंजाब और उसके किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। इस उच्च स्तरीय बैठक में विशेष सचिव कृषि हरबीर सिंह, कृषि निदेशक जसवन्त सिंह, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के अनुसंधान निदेशक डॉ. अजमेर सिंह ढट्ट और पंजाब मंडी बोर्ड और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

- सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के दिए निर्देश
- सोशल मीडिया पर भी लगातार सुनिश्चित करें प्रचार-प्रसार
- कार्यालयों में स्वच्छता का रखें विशेष ध्यान

चंडीगढ़। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के.एम. पांडुरंग ने आज चंडीगढ़ में विभाग के आला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए कि सरकार के विकास कार्यों व जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य प्रभावी तरीके से करें और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।

महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को स्वच्छ व सुन्दर बनाना है, इसी कड़ी में सभी जिलाधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। विशेष अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्री पांडुरंग ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार आमजन के लाभ व कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। ऐसे में विभाग का दायित्व बनता है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी लाभपात्रों को सही ढंग से मिले, इसके लिए प्रचार माध्यमों का समुचित प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक योजनाओं की जानकारी जनता तक भिजवाना सुनिश्चित करें। योजनाओं के प्रचार - प्रसार में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करें। विभागीय प्रचार सामग्री के वितरण पर विशेष ध्यान दिया जाये। महानिदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी लाइव कार्यक्रमों का अवलोकन करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित किया जा रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही सरकार द्वारा समाधान शिविर सहित अनेक सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं और इन शिविरों में आने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण होने पर सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रचारित करते हुए लोगों को सरकार की जन सेवा को समर्पित योजनाओं के बारे में अवगत भी कराया जाए। बैठक में जिला अधिकारियों को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपडेट रखने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक के दौरान अन्य विभागीय गतिविधियों की भी क्रमवार समीक्षा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, संयुक्त निदेशक श्रीमती आंचल भास्कर, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वंदना शर्मा, श्री रणबीर सिंह सांगवान, डॉ साहिब राम गोदारा, संयुक्त निदेशक (प्रेस) सहित मुख्यालय व जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।